राम दरबार

सोना लेई जा रे ...चांदी लेई जा रे.....

इन दिनों कभी सोना कभी चांदी सर चढ़कर बोल रहा है भाव पल पल आसमान छू रहे हैं।सोना चांदी में ये उछाल प्रापर्टी वालों को एक अच्छे बल्लेबाज की तरह पीट रहा है।

सोना कितना सोना है सोने जैसा तेरा दिल ।हर किसी का दिल सोने पे मर मिट रहा है।कमबख्त सोना चीज ही ऐसी है जिसे पाने की ख्वाहिश में अच्छे अच्छों का सोना उड़ा उड़ा है

कभी कहा जाने वाला नींद से ताल्लुक रखने वाला शब्द सोना आज नींदें उड़ाने वाला कहलाने लगा है।

यूं तो सुबह के नास्ते में क्या अमीर, क्या गरीब बिस्किट खाते आए हैं लेकिन नसीब उनके जिनके पास अथाह काला धन है वे न तो ब्रिटानिया न पारलेजीअन्य किसी ब्रांड का बिस्किट खा रहे हैं , कोशिश कर रहे है गोल्ड ही गोल्ड मेरी गोल्ड बिस्किट खाएं ।सोना चांदी धन संग्रह की ये लालसा उनहें कामयाबी के शिखर पर पहुंचायेगी।पर्ची पर सोना चांदी के लाखों हजारों, करोड़ों,अरबों के खेल रोजाना इनकमटैक्स बचाकर आंख मिचौली से खेले जा रहे हैं।गला काट प्रतिस्पर्धा के चलते व्यापारियों की नियत भी गिरगिट सी रंग बदल रही है।कभी विश्वास पर किया जाने वाला वायदा अविश्वास में बदलता जा रहा है नकली सोना चांदी वायदा बाजार में धमाल मचा रहे हैं।इनके चलते भद्र व्यापारी भी एक दूसरे को आंख दिखाते अपना विश्वास खोते ,एक दूसरे के जानी दुश्मन बने जा रहे हैं।सोने चांदी के आगे दिन दहाड़े देश में संगीन अपराध हो रहे हैं। धन लक्ष्मी के आगे दोस्ती मित्रता ताक पर आ ग?ई है।

आम आदमी की हैसियत तो नहीं है पर लालसा जाग्रत हो रही है जो कुछ उसके पास है दांव लगा सोना चांदी खरीद ही ली जाये।इस बात से बैफ्रिक जब औंधे मुंह बाजार गिरेगा ,तब झुमका बरेली के बाजार में नहीं वास्तविक जिंदगी में गिरेगा तब उसके पास सर पीटने के सिवा कुछ हाथ नहीं बचेगा।सोना चांदी के बढ़ते भावों से देश ने करवट बदली है देश के नामी गिरामी छुट भैय्या चोरों की बल्ले बल्ले हो रही है ये शहरों ही नहीं गांवों के मंदिरों ,देवस्थानों पर भगवान के आभूषण चुराने में सेंधमारी कर रहे हैं फिर सांठगांठ कर ओने पोने भाव में बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं।बड़ी शान से कहते हैं -उनके द्वारा यह ईमानदारी और मेहनत से कमाया शुद्ध धन है पकड़े गये तो ले देके छूट ही जाएंगे न पकड़े गये तो स्वर्ण सीढ़ियां चढ़ ही जायेंगे। इनके सपने भी सराफा व्यापारियों की तरह ऊंचे और गुले गुलजार हुए हैं।

जिस तीव्र गति से सोना चांदी में उछाल आया है काश! ये उछाल मेहनतकश किसान की फसलों में आता ।अपनी मेहनत , लागत का सही मूल्य मिल पाता।सृष्टि का पालनहार अन्नदाता परेशान हैं ।सोना चांदी के साथ खेल खेलना सट्टा बाजार है। आज सराफा बाजार सबको आंमत्रित कर रहा है थोड़ा सोने में सुहागा कर लो।बस यही बात फिल्मी अंदाज में कह रहा है सोना लेई जा रे.....चांदी लेई जा रे..।

लाल बहादुर श्रीवास्तव
शब्द शिल्प ,एल आई जी ऐ-15जनता कालोनी मंदसौर मध्यप्रदेश 458001

टीम नबीन में शामिल होने के लिए नेताओं को देनी होगी 'अग्नि परीक्षा'

इंदौर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन इन दिनों चर्चा में छाए हुए हैं। चर्चा है अध्यक्ष बनने के बाद से वह अपनी नई टीम बनाने पर कार्य कर रहे हैं। खबर आ रही है कि अध्यक्ष नितिन नबीन की टीम में शामिल होने वाले नेताओं को अग्नि परीक्षा यानी ऑडिशन देना होगा। इसमें पास होने के बाद ही उनकी टीम का हिस्सा बना जा सकता है। अब सवाल उठता है कि यह किस तरह का ऑडिशन होगा, तो इस पर सूत्रों का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए देश भर से चुने जा रहे भाजपा नेताओं को उनके प्रदर्शन के आधार पर नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की टीम में शामिल किया जाएगा।

भाजपा सूत्रों के मुताबिक, टीम नबीन में शामिल होने वाले नेताओं की अब तक की पूरी राजनीतिक कुंडली का आकलन किया जाएगा। विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव चुनावों के दौरान किस नेता की परफॉर्मेंस कैसी रही इसको भी देखा जाएगा। उसके बाद नेताओं की सूची बनाई जाएगी। फिर उसका संघ, संगठन और सरकार के स्तर पर मंथन किया जाएगा। उस मंथन में एक-एक नाम पर विचार-विमर्श करने के बाद नाम अलग किए जाएंगे। एक सूत्र ने बताया कि उनके प्रदर्शन के आधार पर ही नितिन नबीन के कार्यकाल के दौरान उन्हें व्यापक संगठनात्मक संरचना में स्थान दिया जाएगा। भाजपा के एक नेता ने कहा, जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये नेता चुनाव तैयारियों की निगरानी में अधिक से अधिक समय बिताएंगे और टिकट वितरण से संबंधित निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है। एक अन्य वरिष्ठ नेता ने कहा कि इसका मतलब है कि यह भी है कि नितिन नबीन की नई टीम और उससे जुड़े संगठनात्मक परिवर्तनों में अभी कुछ समय लगेगा। कहा जा रहा कि 45 वर्षीय नितिन नबीन की टीम में नए चेहरों और अनुभवी नेताओं का मिश्रण रहने की उम्मीद है।

- प्रदर्शन के आधार पर ही नितिन नबीन के कार्यकाल के दौरान दिया जाएगा व्यापक संगठनात्मक संरचना में स्थान

पांच राज्यों के चुनाव बनेंगे आधार

पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के एक नेता का कहना है की भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम बनाने के लिए इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों को भी आधार बनाया जाएगा। इस साल असम, तमिलनाडु , केरल, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव हैं। एक भाजपा नेता ने कहा कि नितिन नबीन की टीम युवा और अनुभवी नेताओं को लेकर बनाई जाएगी जो भाजपा, संघ और राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच पुल का काम करेगी।

भाजपा की नई टीम में 55 से कम के नेता

भाजपा 2029 और उससे आगे की राजनीति के हिसाब से भी अपनी गोटियां सेट करना चाहेगी। मतलब,जब भी हो इनमें ज्यादा से ज्यादा युवा चेहरों को जगह मिलना तय है और इसी तरह का बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में भी देखने को मिल सकता है।

नितिन नबीन की नई टीम में पार्टी के ज्यादातर पदाधिकारियों की उम्र 55 वर्ष से कम हो सकती है। मतलब, जिस तरह से पार्टी ने अचानक एक युवा चेहरे को पार्टी की कमान सौंपी है, उसी हिसाब से उनकी नई टीम में युवा नेताओं को भी राष्ट्रीय स्तर पर बड़े रोल में देखा जा सकता है। यह वो टीम हो सकती है, जिसे लेकर पार्टी 2029 और उसके आगे के चुनावों में उतरना चाहेगी।

ये युवा चेहरे पार्टी को जहां नया जुझारू तेवर देने में मदद कर सकते हैं, वहीं इनके माध्यम से दूरगामी राजनीतिक संदेश देने की भी कोशिश रहेगी।

नई टीम में सभी तरह का समीकरण होगा

नीतीन नबीन की नई टीम में ज्यादातर ऐसे नेताओं को प्राथमिकता मिल सकती है, जो भाजपा और आरएसएस की विचारधारा में तप कर उभरे हों। वहीं पार्टी कुछ ऐसे नेताओं पर भी दांव लगा सकती है, जो सामाजिक और राजनीतिक तौर पर पार्टी के संगठन को नई धार दे सकें।

रिपोर्ट में कहा गया है कि संगठन के मौजूदा प्रदेश नेताओं में से भी कुछ लोग नई टीम के हिस्सा हो सकते हैं, वहीं कुछ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सीएम और कुछ पूर्व केंद्रीय मंत्री भी इसका हिस्सा बन सकते हैं।

पार्टी के बाद सरकार में बदलाव के आसार

हालांकि, यह बात प्रधानमंत्री मोदी को छोड़कर कोई नहीं जानता कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल कब होगा। लेकिन, सच्चाई ये है कि मोदी सरकार में अभी जितने मंत्री हैं, उनमें 34 मंत्री 2021 से ही बने हुए हैं।

इनमें से 19 तो कैबिनेट मंत्री हैं। रिपोर्ट के अनुसार मोदी 3.0 के भी कुछ महीनों में दो साल होने को हैं।

ऐसे में मंत्रियों की परफॉर्मेंस और उनके कार्यों में बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है। मतलब, सरकार में अगर कुछ नए युवा चेहरों को लाया जाता है तो कुछ चेहरे संगठन में भी शिफ्ट हो सकते हैं। ऐसे में पार्टी संगठन में बदलाव के बाद ही मंत्रिपरिषद में बदलाव का आधार तैयार हो सकता है।

बदलाव होंगे, लेकिन इसमें अभी वक्त है

वैसे भाजपा के एक पदाधिकारी ने नाम नहीं जाहिर होने देने की शर्त पर एनबीटी ऑनलाइन से कहा है कि परंपरा ये रही है कि पूर्व सीएम या केंद्रीय मंत्री जब संगठन में जाते हैं, तो उन्हें उनकी वरिष्ठता को देखते हुए उपाध्यक्ष या महामंत्री पद का दायित्व दिया जाता है। लेकिन, नितिन नबीन के अध्यक्ष रहते वरिष्ठ नेताओं का उपाध्यक्ष या महासचिव पद पर एडजस्टमेंट इतना आसान नहीं होगा। इसलिए, संगठन और सरकार में बदलाव भले ही तय हों, लेकिन इसमें काफी माथापच्ची है, जिसके चलते समय लगेगा।

राज्यसभा की सीटों पर भी एडजस्टमेंट जरूरी

भाजपा और सरकार के सामने चुनौती ये है कि एक दर्जन से ज्यादा मंत्रियों के पास दो-दो पोर्टफोलियो है। कई नेताओं का राजनीतिक करियर भी आखिरी दौर में है। इनके अलावा अनेक नेताओं का राज्यसभा कार्यकाल भी इस साल खत्म हो रहा है। मसलन, इस साल 70 से ज्यादा राज्यसभा सीट खाली होने वाली है, जिनमें से भाजपा के ही 30 के करीब सांसद हैं।

मौजूदा विधानसभाओं की शक्ति के हिसाब से पार्टी लगभग 33 सांसदों को उच्च सदन में भेज सकती है। मतलब, यह सारा गुणा-गणित भी नितिन नबीन की जिम्मेदारियों की लिस्ट में आने वाली है।

कागजों में सिमटा सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग

मप्र में सामान्य वर्ग की अनदेखी...

इंदौर। मप्र सरकार का दावा है कि उसका फोकस प्रदेश के हर वर्ग के संरक्षण और कल्याण पर है। लेकिन हकीकत यह है कि मप्र में सामानय वर्ग के साथ लगातार अनदेखी हो रही है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सामान्य वर्ग के लिए गठित सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का कही नाम-पता नहीं रख गया है। आयोग कागजों में सिमट कर रह गया है।

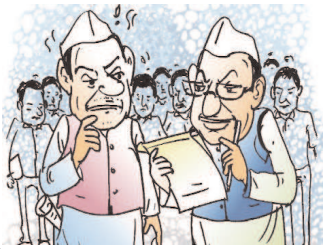

आयोग में पदाधिकारी न होने से सवर्णों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। यही नहीं मुख्यमंत्री मेधावी योजना पर भी बजट का संकट है। जबकि एससी-एसटी, ओबीसी व अल्पसंख्यकों के लिए जहां अलग विभाग है, वहीं योजनाओं और बजट की भरमार है। एससी-एसटी, ओबीसी व अल्पसंख्यकों की समस्याओं को लेकर सरकार हमेशा सजग रहती है। वहीं सामान्य वर्ग को लेकर कभी भी संवेदनशीलता नजर नहीं आती है।

सरकार ने सामान्य वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का गठन तो किया, लेकिन यह केवल कागजों तक सीमित रह गया है। स्थिति यह है कि आयोग में लंबे समय से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी भी पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है। नेतृत्व के अभाव में सामान्य वर्ग के निर्धन लोगों की सुनवाई पूरी तरह ठप पड़ी है, जिससे इस वर्ग में सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर गहरा असंतोष है।

सामान्य वर्ग के लिए कोई प्रभावी तंत्र नहीं

यूजीसी के नए नियमों को लेकर उपजा विवाद भले ही सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद कानूनी रूप से थमता दिख रहा हो, लेकिन इसने मध्य प्रदेश में सामान्य वर्ग की उपेक्षा के पुराने जख्मों को फिर से हरा कर दिया है।

प्रदेश में एससी-एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए तो समर्पित विभाग और वित्त निगम सक्रिय हैं, लेकिन सामान्य वर्ग के कल्याण के लिए कोई प्रभावी तंत्र नजर नहीं आ रहा है।

इसे लेकर अब समाज के विभिन्न हलकों में वर्ग भेद और विभाजन की लकीरें गहरी होने की चिंता जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में संवैधानिक समानता के दावों के बीच प्रशासनिक ढांचा वर्गों में बंटा नजर आता है।

अल्पसंख्यक समुदायों के सर्वांगीण विकास के लिए वर्ष 1991 से ही अलग विभाग काम कर रहा है। इसी तरह एससी-एसटी और ओबीसी वर्गों की समस्याओं और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पृथक विभाग व वित्त विकास निगम गठित हैं। इन वर्गों की शिकायतों की सुनवाई के लिए राज्य और केंद्र स्तर पर शक्तिशाली आयोग भी मौजूद हैं।

इसके उलट, सामान्य वर्ग के लिए न तो कोई अलग विभाग है और न ही शिकायतों की सुनवाई के लिए कोई प्रभावी आयोग।

मप्र भाजपा मुख्यालय में नेताओं के ठाठ-बाट में कटौती

न नाश्ते की टेबिल सज रही, न होटल से मनचाहा खाना आ रहा

इंदौर। मप्र भाजपा में पिछले तीन महीने के भीतर हुए संगठनात्मक बदलावों का असर अब पार्टी के भीतर भी दिखाई देने लगा है। सबसे बड़ा बदलाव प्रदेश कार्यालय में नेताओं के ठाठ-बाट में देखने को मिल रहा है। अब न नाश्ते से नेताओं के टेबलें सज रही हैं और न ही बाजार से मनपसंद खाना आ रहा है। यहां तक के थोक में आने वाले नारियल पानी भी बंद हो गए हैं। प्रदेश कार्यालय में अन्य फिलूलखर्ची भी रुक गई हैं।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सादगी का असर अब पार्टी में दिखाई देने लगा है। जिसकी शुरूआत खंडेलवाल ने खुद से की है। वे न तो पार्टी के वाहन का उपयोग करते हैं और न ही अन्य किसी तरह की सुविधाएं लेते हैं। अब भाजपा कार्यालय में आगंतुकों का भी वीवीआईपी सत्कार नहीं हो रहा है। साधारण कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेताओं तक के लिए एक ही तरह के चाय-नाश्ते का बंदोबस्त कर दिया है। पहले पार्टी पदाधिकरी, कार्यालय स्टाफ एवं अन्य के लिए चाय की व्यवस्था थी, लेकिन अब सभी के लिए चाय-कॉफी की व्यवस्था कर दी गई है। कार्यालय परिसर में आने वाले आम कार्यकर्ता या आम नागरिक के लिए मशीन से चाय की व्यवस्था है। साथ ही पैकड वाटर की जगह अब पानी की बोतल, गिलास और जग रखवाएं गए हैं।

वाहन सुविधाओं में कटौती-भाजपा प्रदेशाध्यक्ष खंडेलवाल ने अपने स्तर से किसी तरह की रोक नहीं लगाई है, लेकिन उनकी साधारण जीवन शैली एवं सुविधाओं से दूरी का असर दूसरे नेताओं पर दिखाई दिया है। जो नेता पार्टी के खर्च पर वाहन सुविधाएं लेते थे। उसमें कटौती हो गई है। सिफ वे नेता ही पार्टी के वाहन का उपयोग कर रहे हैं, जिन्हें पार्टी की ओर से सुविधाएं उपलब्ध कराई गईहैं।

प्रदेश में 10 हजार महिलाएं जांचेंगी पानी की गुणवत्ता

इंदौर। इंदौर दूषित जल से मौतों के बाद प्रदेश सरकार पानी की गुणवत्ता को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में जल परीक्षण के लिए 10 हजार महिला अमृत मित्रों की तैनाती की जाएगी।

- जल एवं सीवेज के काम में लेतलाली करने वाले ठेकेदार ब्लैकलिस्ट

- नगरीय प्रशासन आयुक्त ने योजनाओं की समीक्षा में दिए निर्देश

नगरीय प्रशासन आयुक्त एवं मप्र अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक संकेत भोंडवे ने नगरीय निकायों की जल प्रदाय एवं सीवरेज योजनाओं की समीक्षा के दौरान यह निर्देश निर्देश।

उन्होंने काम में लेटलाती करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि सभी परियोजनाओं में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करें।

भोंडवे ने कहा कि जल प्रदाय की लाइन किसी भी स्थिति में सीवरेज लाइन से न मिले, जिससे पेयजल की स्वच्छता बनी रहे। उन्होंने जल परीक्षण के लिए एमपीयूडीसी के माध्यम से 10 हजार महिला अमृत मित्र तैनात करने के भी निर्देश दिए।

ह अमृत मित्र जल स्वच्छता की जांच करेंगी। उन्होंने कहा कि एमपीयूडीसी की सभी परियोजनाओं की समीक्षा अब हर माह की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता वे स्वयं करेंगे। उन्होंने पूर्ण हो चुकी 35 नगरीय निकायों एवं प्रगतिरत 52 नगरीय निकायों की जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रोजेक्ट्स की विस्तृत समीक्षा की।

एकीकृत विकास परियोजना बुधनी के ठेकेदार वाज इंडिया को टर्मिनेट करने एवं ब्लैक लिस्ट करने, पसान के मुख्य ठेकेदार द्वारा नियुक्त सब कांट्रेक्टर कात्यानी, शहडोल सीवरेज में मुख्य ठेकेदार द्वारा नियुक्त सब कांट्रेक्टर ईफिल तथा सांची सीवरेज परियोजना के ठेकेदार 3 आरएम को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए गए। वही ईपीसीएल को प्रदर्शन न सुधरने पर टर्मिनेट करने की चेतावनी दी गई।

प्रदेश युवा मोर्चा की नई टीम पर मंथन

श्याम टेलर की पहली टीम में दिखेगी सोशल इंजीनियरिंग

इंदौर। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद श्याम टेलर की पहली प्रदेश टीम को लेकर संगठन के भीतर हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक, टीम की औपचारिक घोषणा से पहले फाइनल राउंड की बातचीत चल रही है और इस पूरी कवायद में सोशल इंजीनियरिंग देखने को मिलेगी। संगठन से जुड़े अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि इस बार की टीम में प्रदेश के हर हिस्से से नेताओं को जगह दी जाएगी। सूत्रों का कहना है की श्याम टेलर की टीम में जातीय, क्षेत्रीय संतुलन पर विशेष फोकस रहेगा। वहीं संगठन के भीतर जिनकी छवि ग्राउंड पर काम करने वाले नेता की रही है, उन्हें महत्व दिया जाएगा। वहीं भाजपा संगठन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दोनों में कार्य अनुभव रखने वाले नेताओं को संगठन और कम्युनिकेशन ब्रिज के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि मीडिया और विचारधारा, दोनों मोर्चों पर पकड़ रखने वाले युवाओं को प्रदेश टीम में में जगह दी जाएगी।

पुलिसकर्मियों को नहीं मिल रहा साप्ताहिक अवकाश

मुख्यमंत्रियों की घोषणा पर भी आज तक अमल नहीं

इंदौर। संभवत- प्रदेश में यह पहला मामला होगा, जब एक नहीं तीन-तीन मुख्यमंत्रियों ने सार्वजनिक मंच से कोई घोषणा की और वह पूरी नहीं हो पाई। हम बात कर रहे हैं प्रदेश में आरक्षक से लेकर थाना प्रभारी तक के साप्ताहिक अवकाश की। मैदानी स्तर पर इनकी संख्या लगभग 70 हजार हैं, जिन्हें अवकाश नहीं मिल पा रहा है। वर्ष 2014 में सबसे पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों के लिए साप्ताहिक अवकाश की घोषणा की। इस पर अमल नहीं हो पाया।

इसके बाद कांग्रेस सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमल नाथ ने वर्ष 2019 में घोषणा की। अमल भी शुरू हुआ, लेकिन पुलिस बल की कमी के चलते एक वर्ष के पहले ही अवकाश देना बंद हो गया। बाद में भाजपा की सरकार आई तो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अगस्त 2020 में फिर साप्ताहिक अवकाश की घोषणा की। कुछ जिलों में व्यवस्था प्रारंभ भी हुई पर धीरे-धीरे बंद हो गई। वर्ष 2021 में उस समय के गृह मंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा ने कहा, पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा, पर अमल नहीं हुआ।

सीएम मोहन यादव भी कर चुके हैं एलान

मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने भी एलान कर रखा है। एक साल हो चुके हैं, पर पालन नहीं हो रहा है। उप पुलिस अधीक्षक और ऊपर के अधिकारियों को अवकाश मिल रहा है, लेकिन आरक्षक से लेकर निरीक्षक संवर्ग तक मैदानी अधिकारियों को नहीं। जिलों में अवकाश की व्यवस्था का रोस्टर बनाने की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षकों दी गई थी।

बल की कमी के चलते पुलिस अधीक्षकों ने अवकाश देना बंद कर दिया, जिससे एक बार कमल नाथ के समय और दूसरी बार शिवराज सिंह चौहान के समय अवकाश की व्यवस्था टप हो गई।

दरअसल, प्रदेश में पुलिस आरक्षक से लेकर एएसपी तक के एक लाख 26 हजार पदों में से 25 हजार से अधिक रिक्त हैं। नए थाने बनने पर ही पुलिस बल स्वीकृत किया जा रहा है।

जिस तरह से आबादी और अपराध बढ़ रहा है, उस मान से नए थाने नहीं खुल रहे हैं। ऐसे में एक तो आवश्यकता के अनुसार बल नहीं है। दूसरा, रिक्तियां होने के कारण अवकाश नहीं मिल पा रहा है।

इस संबंध में डीजीपी कैलाश मकवाणा ने कोई जवाब नहीं दिया। अन्य राज्यों की स्थिति कर्नाटक सरकार ने दो दिन पहले ही पुलिसकर्मियों को जन्म दिवस और शादी की सालगिरह पर अवकाश देने का निर्णय लिया है।

हालांकि, अधिकतर राज्यों में स्थिति मप्र की तरह की है। हरियाणा में वर्ष 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अवकाश की घोषणा की लेकिन पालन नहीं हुआ।

तमिलनाडु में तो एक पुलिसकर्मी ने साप्ताहिक अवकाश के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई है।